समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

मोदी सरकार के प्रस्ताव से शशि थरूर को राजनीतिक लाभ, संसदीय समितियों का कार्यकाल बढ़ सकता है

Publisher

Published on 27 Sep 2025

केंद्र सरकार संसदीय समितियों के **कार्यकाल को बढ़ाने** पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार, संसदीय समितियों का वर्तमान एक साल का कार्यकाल बढ़ाकर **दो साल तक** किया जा सकता है। इस कदम को संसद में कार्यक्षमता और स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।

विशेष रूप से, कांग्रेस सांसद **शशि थरूर** इस फैसले से राजनीतिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। थरूर पहले से ही विभिन्न संसदीय समितियों में सक्रिय हैं और उनका अनुभव तथा दक्षता इस प्रस्ताव के लागू होने पर और महत्वपूर्ण हो जाएगी।

संसदीय समितियों का महत्व

संसदीय समितियां संसद के कार्य को और प्रभावी बनाने का एक प्रमुख साधन हैं। ये समितियां **कानूनों की समीक्षा, बजट पर निगरानी, नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन** करती हैं। आमतौर पर इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

हालांकि, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर काम करने वाले सांसदों के लिए लंबा कार्यकाल **नीतिगत स्थिरता और बेहतर परिणाम** सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे में शशि थरूर जैसे अनुभवी सांसदों के लिए यह अवसर **राजनीतिक और प्रभावशाली** रूप में उभर सकता है।

केद्रं सरकार की योजना और उद्देश्य

केंद्र सरकार का उद्देश्य संसदीय समितियों की कार्यक्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाना है। लंबे कार्यकाल से समितियों को अधिक **सतत और प्रभावी निर्णय लेने** का अवसर मिलेगा।

सरकार का यह भी मानना है कि एक साल का कार्यकाल अक्सर निर्णयों और रिपोर्टिंग में समयाभाव का कारण बनता है। दो साल

का कार्यकाल सांसदों को **गहराई से अध्ययन और नीति निर्माण मे योगदान** देने का अवसर देगा।

शशि थरूर को लाभ कैसे होगा

कांग्रेस सांसद **शशि थरूर** पहले से ही **संसदीय समितियों मे प्रभावशाली भूमिका** निभा रहे हैं। उनकी वक्तृत्व क्षमता, नीति समझ और अनुभव उन्हें इस फैसले से लाभान्वित कर सकते हैं।

यदि कार्यकाल दो साल का हो जाता है, तो थरूर जैसे सांसद लंबी अवधि तक **विशेषज्ञता के साथ समिति के निर्णयों और रिपोर्टों को प्रभावित** कर सकते हैं। यह उनके **राजनीतिक अनुभव और प्रभाव** को और मजबूत करेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम **कांग्रेस और थरूर जैसे अनुभवी सांसदों के लिए रणनीतिक अवसर** प्रस्तुत कर सकता है। इससे न केवल उनका अनुभव संसद में और महत्वपूर्ण बनता है, बल्कि राजनीतिक दृश्य में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है।

संसदीय प्रक्रिया और विपक्ष की भूमिका

संसदीय समितियों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में चर्चा के लिए भेजा जाएगा। इसमें विपक्षी दल भी अपनी राय रखेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल अगर लागू होती है, तो संसद की कार्यप्रणाली में **नवाचार, विशेषज्ञता और गहन विश्लेषण** की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही संसदीय समितियों की रिपोर्ट और निर्णय **लंबी अवधि तक नीति निर्माण मे सहायक** होंगे।

राजनीतिक रणनीति और प्रभाव

केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लंबे कार्यकाल से अनुभवी सांसदों का प्रभाव बढ़ेगा और उनकी **नीति निर्माण मे भागीदारी** सुनिश्चित होगी।

शशि थरूर के मामले में, यह कदम उन्हें न केवल **संसदीय कार्यों मे अधिक प्रभाव** देगा बल्कि उन्हें पार्टी और जनता के बीच **राजनीतिक प्रतिष्ठा और साख** भी बढ़ाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय केवल संसदीय कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनाव और पार्टी की रणनीति में भी इसका **सकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है।

केंद्र सरकार का संसदीय समितियों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव **संसदीय कार्यक्षमता, नीति निर्माण और विशेषज्ञता** को बढ़ावा देगा। इस कदम से अनुभवी सांसद जैसे शशि थरूर **राजनीतिक और पेशेवर दोनों दृष्टि से लाभान्वित** हो सकते हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.